India-China Border Dispute and Formation of Nation State in Asia

Mizuno Mitsuaki*

The border dispute lies most seriously in India-China relations. In this article, I analyze this topic from the view of formation of nation states in Asia. Then, what is 'nation state' ? Clear definition is needed. Here, I define 'nation state' as B. Anderson states it. Namely nation state consists of nation, clearly defined territory and exclusive sovereignty. Nation state has been born in Europe originally, not in Asia. Through the process how it was formed in Asia, I'll discuss the border, by which one nation state is distinguished from another one.

By this perspective, I will analyze Simla Conference as its historical background. Simla Conference was a tripartite conference held in Simla, India in 1913-1914. Originally in Asia, especially in East Asia, there existed Chinese traditional world order, as J. K. Fairbank called it. In this world order, center - periphery relationship is tributary one. That is to say, the relationship between Tibet and Chinese central government was tributary, too. But so-called western impact, notably after concluding Beijing Treaty in 1860, East Asia was integrated into European international system, namely nation state system. In this process, Chinese central government lost its cohesion , and its periphery geared up centrifugal force and sought its identity. Tibet sought for its identity and Chinese central government forced Tibet not to become independent.

This caused Chinese central versus Tibet conflicts. These conflicts got violent in the early years of the 20 th century, and expanded to the area near the border of Assam. The British had to mediate them in order to keep the area silent. The Conference was finally summoned to meet at Simla. Sir Arthur Henry McMahon, the Secretary in the Indian Foreign Department, was the British Plenipotentiary, Lon-chen, that is Chief Minister, Shatra was the Tibetan Plenipotentiary, and Ivan Chen was the Chinese Plenipotentiary. The discussions started on October 1913, extended over six months, and dealt very fully with the whole Tibetan question. The Tibetan Government claimed all territory in which the population was almost entirely Tibetan. Far from agreeing to this, the Chinese Government claimed all Tibetan territory which Chao Erh Feng had succeeded in occupying

*Osaka University of Foreign Studies

when his power was at its height. The British proposed the Simla Convention, according to which Tibet was divided into two zones, 'Outer Tibet' and 'Inner Tibet', Chinese suzerainty over the whole of Tibet was recognized, but China engaged not to convert Tibet into a Chinese province, Great Britain engaged not to annex any portion of Tibet, and the autonomy of Outer Tibet was recognized. The boundary between Outer Tibet and India was McMahon Line. On the 27 th April 1914, it was initialled by the three Plenipotentiaries. Two days after initialling, the Chinese Government disavowed the action of its Representative and refused to permit him to proceed to full signature. The negotiations with China broke down on one point only; namely, the frontier to be established between China and [Inner] Tibet. Although in July, the British and Tibetan Plenipotentiaries signed it. Two or three weeks later, the Great War [World War I] broke out and threw Tibetan affairs into the background. (Charles Bell, *Tibet Past and Present*, New Delhi, 1992 (reprinted edition), p. 156.)

To summing up, the origin of India-China border dispute remains the question whether McMahon Line and Simla Convention is legal or illegal only British and Tibetan Plenipotentiaries accepted and signed.

In 1950, the next year after the founding of a country, People's Republic of China sent and stationed People's Liberation Army into Tibet, to annex it. China converted the largest area since Qing dynasty into the territory as the nation state, People's Republic of China. According to China, Tibet is an integral part of China and has had no right to conclude any international treaties with any foreign powers. Sending and stationing People's Liberation Army in Tibet means the conversion Chinese traditional world order into European international system. But the Indian government did not understand this logic, and claimed the validity of McMahon Line as the boundary between India and China. The border dispute was born here.

In fact, India and China tried in vain to avoid the border conflicts. At last, border "war" as Neville Maxwell said in his *India's China War*, occurred in October 1962.

This India's misapprehension about China's logic incurred border clash. On the other hand China did not do the best to explain its logic and conversion of international system.

Until today there are few scholarly works from the point of the view of the conversion of international system in East Asia, or China. I hope to analyze and discuss this topic from this point more.

एशिया में आधुनिक राष्ट्रीय देश का उदय और भारत-चीन सीमा समस्या

मिज़ुनो मित्सुआकि

(ओसाका विदेशी भाषाएँ विश्वविद्यालय)

भारत-चीन संबंध में सीमा समस्या तो सबसे महत्वपूर्ण विचाराधीन है। इस मज़्मून के निशाने ये हैं कि आधुनिक राष्ट्रीय देश के दृष्टिकोण से सीमा समस्या के विश्लेषण करना और एशिया में कैसे आधुनिक राष्ट्रीय देश प्राप्त हुआ।

सबसे प्रथम "आधुनिक राष्ट्रीय देश" की परिभाषा करना चाहता हूँ। बिना परिभाषा, हम सीमा समस्या को अच्छी तरह से नहीं सोच सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रीय देश होने के लिए तीन चीजें ज़रूरी है। एक तो राष्ट्र या देशवासी है। राष्ट्र अपने आपस से उदय नहीं। राष्ट्र बनावटी समुदाय है। दूसरा तो वह राज्य या स्थान है जो स्पष्ट रूप से निश्चित है। तीसरा तो प्रभुता है। पर आधुनिक राष्ट्रीय देश सब से पहले यूरोप मैं, नहीं एशिया मैं बन गया। इसलिए आधुनिक राष्ट्रीय देश कैसे एशिया मैं प्राप्त हुआ, इसके विश्लेषण करना ज़रूरी है। "सीमा" तो क्या है? सीमा तो एक आधुनिक राष्ट्रीय देश को दूसरे से अलग करनेवाला सीमा है।

सबसे पहले, सिमला काँफलेंस को सोचूँगा। यह सम्मेलन सन् १९१३ से सन् १९१४ तक भारत के सिमला में आयोजित किया गया। मैं इस सम्मेलन को भारत-चीन सीमा समस्या के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विश्लेषण करता हूँ।

परंपरागत चीन में वह विश्व सिस्टम होता था जो केंद्र - पड़ोस संबंध तो खराज़ - भेंट संबंध है। इस संबंध को जे० के० फेआबैंक चीनी विश्व ऑडर कहते हैं। केंद्रीय चीन और तिब्बत संबंध भी ऐसा संबंध था। तिब्बत केंद्रीय चीनी सरकार (बेइजिन सरकार) को खराज़ भेजता था, और केंद्रीय चीनी सरकार तिब्बत को भेंट भेजता था। लेकिन इस परंपरागत चीनी विश्व सिस्टम बेइजिन संधि (सन् १८६० में) से , विशेषकर यूरोपीय आघात से डिग गया था। और केंद्रीय चीनी सरकार का अभिकेंद्र बल कमजोर हुआ। इसके साथ साथ चीन - तिब्बत संबंध भी न्यून हुआ था। एक ही समय में चीन और तिब्बत में विवाद हुआ। इस विवाद को बीच - बचाव करने के लिए अंग्रज़ी सरकारने सिमला काँफलेंस तैयार किया।

चीन को चीनी साम्राज्य से आधुनिक राष्ट्रीय देश के रूप में चिमटना चाहिए। वह तिब्बत को अपने राज्य के एक भाग बनाकर चींन राज्य के सबसे बड़े राज्य को अपना (चीनी) राज्य बना चाहती थी। पर तिब्बतको ही चीन की नीति पसंद नहीं। तिब्बत उस स्वायत्तता बरक़रार रखना चाहता था, जिसको तिब्बत चींन राज्य के दौरान रखता था। चीन और तिब्बत में यह अंतर था कि चीन - तिब्बत सीमा कहाँ रखनी चाहिए। इस चीन - तिब्बत विवाद को बीच -बचाव के लिए अंग्रज़ी सरकारने संधि का प्रस्ताव

दिया। इस प्रस्ताव के अुनसार, तिब्बतको दो खंडों में विभाजित करना था। एक खंड तो भीतरी तिब्बत है, दूसरा खंड तो बाहरी तिब्बत है। भीतरी तिब्बत ही चीन का एक भाग पर चीनी प्रदेश नहीं होगा। भीतरी तिब्बत, बाहरी तिब्बत तथा चीन में अंतर्रोधीन क्षेत्र है। बाहरी तिब्बत के पास स्वायत्ता है, लेकिन चीनी गणराज्य अधिराजत्व इसपर रखता है। इस विवादास्पद प्रस्ताव को सिमला संधि कहते हैं। पहले ही चीनी सरकारने इसे स्वीकार किया। अंत में बाहरी तिब्बत - भीतरी तिब्बत सीमा रेखा पर चींचपड़ करके सिमला संधिको स्वीकार नहीं किया था। केवल अंग्रज़ी और तिब्बती पूर्णाधिकारी राजदूत इस सिमला संधि को स्वीकार किया था। इस संधि में लिखी गई बाहरी तिब्बत - भारत सीमा रेखा को माक्माहॉन लाइन कहते हैं। और बाद में इस लाइन का कानूनी वैध के बारे में भारत और चीन लोक गणराज्य में विवाद हुआ। "मक्माहॉन" तो अंग्रज़ी पूर्णाधिकारी राजदूत का नाम है।

सन् १९४७ में भारत आज़ाद हुआ। और वह अंग्रेज़ का उत्तराधिकारी था, वे संधियों को स्वीकार किया जिनका भारत की आज़ादी के पहले अंग्रेज़ी सरकारने समापन किया गया था। अंग्रेज़ी सरकारने "भारत आज़ाद एक्त" बना दिया और इस कानून के अुनसार भारतको सत्ता दी। पर एक भारत दो आधुनिक राष्ट्रीय देशोंमें विभाजित किया गया। भारत और पाकिस्तान।

दोनों आधुनिक राष्ट्रीय देशोंको राष्ट्रीय संघट करना चाहिए । विभाजन से बहुत सी गंभीर समस्याएँ भी हुईं । उदाहरण के लिए बंगाल प० बंगाल और पूरब पाकिस्तान में विभाजित किया गया । पंजाब भी विभाजित किया । दोनों नई सरकारोंको इन गंभीर समस्याओं का राजनैतिक तथा आर्थिक समाधान निकालना चाहिए। और आज़ भी समाधान निकालना चाहिए ।

चीनको सन् १८६० की बेइजिन संधि के बाद, परंपरागत चीनी विश्व सिस्टम के केंद्र से आधुनिक राष्ट्रीय देशी विश्व सिस्टम का एक सदस्य बना चाहिए । परंपरागत चीनी विश्व सिस्टम कन्फ़्यूशसवाद पर रहता है, और कन्फ़्यूशसवाद विश्वजनीन है । इसलिए कन्फ़्यूशसवाद की बजाय कोई विश्वजनीन विचार को खोजना चाहिए । समाजवादी ही इस विश्वजनीन विचार है । ऐसी स्थितिमें सन् १९४९ में चीनी लोक गणराज्य का जन्म हुआ । चीनी लोक गणराज्य दो राजनैतिक सिस्टमोंपर रहता है । पहला तो परंपरागत चीनी विश्व सिस्टम (कन्फ़्यूशसवादी सिस्टम) है, दूसरा तो आधुनिक राष्ट्रीय देशी सिस्टम है ।

सन् १९५० में चीनी लोक गणराज्यने तिब्बत में जन - विमुक्ति सेना भेजी । भेजने का अर्थ यह है कि चींन राज्य के दौरान सबसे बड़ा क्षेाको आधुनिक राष्ट्रीय देश का भाग बनाना चाहता था । इस समय से भारत सरकारने उस माक्महॉन लाइन

को कानूनी विधिसम्मत भारत – चीन सीमा रेखा कहने लगा । पर चीनी सरकार इस दावा को स्वीकार नहीं कर सकती । सर्वप्रथम, चाीन (चीनी गणराज्य और चीनी लोक गणराज्य) सिमला संधि को स्वीकार नहीं किया । अगर चीन इस भारत के दावे को स्वीकार करे, तो चीन तिब्बतको विदेशी सरकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि का समापन करनेवाला अधिकार देंगा । अगर तिब्बत के पास अंतर्राष्ट्रीय संधि का समापन करनेवाला अधिकार हो, तो सन् १९५० में जन – विमुक्ति सेना भेजना आक्रमण होगा । तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि का समापन करनेवाला, आधुनिक राष्ट्रीय देश का परमावश्यक अधिकार है ।

सन् १९५९ में तिब्बत में विशेषकर ल्हासा में प्रति – चीनी केंद्रीय सरकार देंगे हुए । इसके साथ साथ दालाई लामा भारत में राजनीतिक शरण ली । भारत सरकार ने यह राजनीतिक शरण दे गया था । दालाई लामा भारत में शरणाथी सरकार बनाना चाहते थे। इसलिए भारत – चीन संबंध ख़राब हो गया । भारत और चीनने इस स्थिति में खोज निकालने के लिए कई बार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया । सरकारी सम्मेलन का आयोजन भी किया । पर भारत सिमला संधि वैध कहने लगा । और चीन अवैध कहने लगा । इससे भारत – चीन में विवाद हुआ । सन् १९६२ में बार बार छोटे सशस्त्र टक्कर हुई । अधिक से अधिक

सशस्त्र टक्कर बड़ी ही हुई । दोनों सरकारोंने अपनी अपनी सेना भेजी, सीमा रेखा युद्ध हुआ । पर केवल एक महिने के बाद चीनी सरकारने एक तरफ़ा युद्ध - विराम घोषित किया और अपनी सेना युद्ध के पहले सीमा रेखा तक वापस की ।

महत्वपूरण बात यह है कि "क्या सिमला संधि वैध या अवैध है ? " विवाद केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चीज़ नहीं । इसका अर्थ उस अंतर में होता है कि भारत और चीन कैसे आधुनिक राष्ट्रीय देश बन गए । भारतने कहा कि भारत अंग्रेज़ी की उत्तराधिकारी के कारण सिमला संधि ही वैध है । चीनने कहा कि दो कारणों से सिमला संधि अवैध है । पहला कारण यह है कि चीनी गणराज्य का पूर्णाधिकारी राजदूतने सिमला संधि को स्वीकार नहीं किया । दूसरा कारण तो यह है कि चीनी साम्राज्य, चींन के दौरान में सबसे बड़ा क्षेत्र को चीनी लोक गणराज्य के भाग बनाना चाहिए । विशेषकर दूसरा कारण चीनी साम्राज्य का विचार से प्रभावित होता है ।

इस तरह भारत - चीन सीमा समस्या का मूलकारण यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे आधुनिक राष्ट्रीय देश बन गया, यह प्रक्रिया अलग है ।

एशिया में आधुनिक राष्ट्रीय देश बनने से बहुत सी समस्याएँ हुईं । भारत - चीन सीमा समस्या इनमें एक है ।

अध्ययन को अधिक बढ़ाने के लिए ---

मैं भारत - चीन सीमा विवाद (समस्या) के अध्ययन से एशिया में आधुनिक राष्ट्रीय देश कैसे बनने का ऐतिहासिक प्रक्रिया पढ़ना चाहता हूँ। मैं इस विषय का अध्ययन ओसका विदेशी भाषाएँ विश्वविद्ध्यालय के विदेशी भाषा भाग के छात्र होने के समय से अभी तक करता हूँ। और भविष्य में, अभी से भी, यह अध्ययन करूँगा।

पूर्वोक्त तरह, आधुनिक राष्ट्रीय देश का उदय पहले ही यूरोप में हुआ। यह देश एशिया में कैसे बनने के अध्ययन का समय में, इसका परिभाषा अधिक से अधिक ठीक से करना चाहिए। ठीक परिभाषा के बिना, मेरा विश्लेषण ऊपरी होगा। फिर भी इस परिभाषे को भारत और चीन की स्थान पर ठीक बैठ जाऊँगा।

भारत तो सन् १९४७ तक अंग्रेज़ी उपनिवेश था, आधुनिक राष्ट्रीय देश नहीं । पर अंग्रेज़ आधुनिक राष्ट्रीय देश की तरह भारत का प्रबंध किया। भारत ही आधुनिक राष्ट्रीय देशी विश्व सिस्टम में "मिथ्य आधुनिक राष्ट्रीय देश" होता था। उदाहरण के लिए भारत आज़ादी के पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त

राष्ट्र संघ का एक सदस्य था । जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ, तभी भारत इसका सदस्य हो गया है ।

चीन के आधुनिक राष्ट्रीय देश बननेवाले का रास्ता भारत का सेभिन्न होता है । चीन के पास अपना परंपरागत विश्व सिस्टम था । इसका विशिष्ट यह है कि केंद्र - घरा संबंध ख़राज संबंध है। पर यह संबंध १९वीं शति का उत्तरार्ध से यूरोपी चोट से नाश गया। चीनको अपनी परंपरागत विश्व सिस्टम रखते हुए आधुनिक राष्ट्रीय देश होना चाहिए ।

१९वीं शती से ऐसे राजनैतिक इतिहास में चीनको अपने क्षेत्र साफ़ करना चाहिए । सन् १९११ में चींन, जो चीनी परंपरागत विश्व सिस्टम में अंतिम साम्राज्य है, निकल गया और चीनी गणराज्य, जो आधुनिक राष्ट्रीय देश है, का जनम हुआ । तथी सीमा रेखा कहाँ होनेवाली समस्या अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो गई । इसी तरह भारत - चीन सीमा रेखा को अप्रत्यक्ष रूप से साफ़ करने के लिए सिमला काँफ़लेंस तैयार हुआ और इस सम्मेलन में भारत - चीन सीमा रेखा के रूप में "माक्महॉन लाइन" निर्धारित किया गया । मैंने "अप्रत्यक्ष रूप से" का प्रयोग किया । क्योंकि सिमला कॉफ़लेंस तो उस चीन (केंद्रीय सरकार) - तिब्बत विवाद को शांत करने के लिए तैयार किया गया जो १९वीं शती के अंत से निकल आया । इस सम्मेलन का अर्थ भारत -

चीन सीमा रेखा साफ़ करना नहीं। अंत में सिमला काँफ़लेस टूट गया। क्योंकि चीनी पूर्णाधिकारी दूतने इस सिमला संधि को स्वीकार नहीं जो अंग्रज़ी पूर्णाधिकारी दूतने संधि का प्रस्ताव के रूप में बना गया था। पर तिब्बती और अंग्रेज़ी पूर्णाधिकारी दूतोंने इस संधि को स्वीकार किया गया। इसी तरह मक्महॉन लाइन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दृष्टि से अंग्रेज़ी (भारत) – तिब्बत सीमा रेखा बन गई। यह भारत – चीन सीमा विवाद का आरंभ है।

१९५० के पहले दशक में भारत – चीन संबंध बहुत अच्छा था। दोनों सरकारोंने सन् १९५४ में "पंचशील" बना गया। लेकिन १९५० के अंतिम दशक में चीन के भारत से संबंध बुरा हुआ था। आज तक बहुत से लोग कहते हैं कि इसी कारण चीन में अर्थव्यवस्था – मंग है। पर कारण एक ही है न ? बहुत से विश्लेषण करना ज़रूरी है।

सीमा विवादने सन् १९६२ में सशस्त्र टक्कर उपस्थित की। यह सशस्त्र टक्कर थोड़ी देर में अंत हो गई। लेकिन सीमा समस्या तो आज भी होती है।

क्यें हल नहीं निकल सकता है ? मैं ऐसा सोचता हूँ कि चीन में दो विश्व सिस्टम, परंपरागत चीनी विश्व सिस्टम तथा आधुनिक राष्ट्रीय देशी विश्व सिस्टम, का आपसी संबंध को समझने के बिना, भारत सरकारने चीन सरकारको माक्महॉन लाइन स्वीकार

करने का माँग किया । भारत का माँग आधुनिक राष्ट्रीय देशी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर होता था । मैं आगे के अध्ययन में चीन में परंपरागत कन्फ़्यूशसवादी विश्व सिस्टम तथा आधुनिक राष्ट्रीयदेशी सिस्टम की अंतराक्रिया का विश्लेषण करना चाहता हूँ । इसी विश्लेषण आज तक नहीं किया गया है । मैं इस विश्लेषणको ध्यान दूँगा ।

गैर यूरोपीय स्थान, भारत और चीन, में कैसे आधुनिक राष्ट्रीय देश का जनम हुआ, इसको आधुनिक राष्ट्रीय देशी सिस्टम के जनम के पहले ही विश्लेषण करना का अर्थ यह है कि आज तक के विदेशी अनुसंधान में नया विचार लेना है । आज तक विदेशी अनुसंधान केवल "आधुनिक राष्ट्रीय देश" को देख रहा है ।

और आजकल विश्व के अनेक भागों में क्षेत्रीय संघट तथा क्षेत्रीय विवाद के कारण आधुनिक राष्ट्रीय देश डिगते हैं । आधुनिक राष्ट्रीय देशीय सिस्टम सभी विश्वको ढकने के पहले विश्व के पास अपने अपने सिस्टम, उदाहरण के लिए चीनी परंपरागत सिस्टम, मुसलमान विश्व सिस्टम आदि, होते थे । इसलिए आधुनिक राष्ट्रीय देशी सिस्टम के विश्लेषण करने से विश्व के अनेक विभागों के पास अपने अपने विश्व सिस्टमों को भी देख सकता है ।

फिर भारत – चीन सीमा समस्या के विश्लेषण करने से

आज के "आधुनिक राष्ट्रीय देशीय सिस्टम" का अर्थ क्या, यह प्रशन सोचूँगा। और भविष्य विश्व सिस्टम को भी सोचूँगा। इस के लिए मैं केवल जापान में ही नहीं, विदेश में भी खोज कर्तों के साथ अध्ययन करना चाहत हूँ।